P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-8* (Part-1) November- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

डिजिटल इंडिया का भारतीय समाज पर परिवर्तनकारी प्रभाव

मानसिंह मीना
सह आचार्य,
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय आर.डी. गर्ल्स कॉलेज,
भरतपुर, राजस्थान

सारांश

डिजिटल यात्रा की कहानी परिवर्तन और समावेशन की गाथा रही है। 2015 में सरकार द्वारा शुरू किये गये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था ओर डिजिटल तरीके से सशक्त समाज के रूप में विकसित करना था। पारदर्शिता, समावेशन, उत्पादकता और कार्यकुशलता बढ़ाकर किये जा रहे इस परिवर्तनकारी विकास का अंतर्निहित आधार टेक्नोलॉजली है।

मुख्य शब्द : डिजिटल इण्डिया, सूचना प्रबंधन, नागरिक सशक्तिकरण ।

प्रस्तावना

डिजिटल इण्डिया के तहत की जा रही पहल और उसके साथ ही टेक्नोलॉजी में हो रहे विकास ने भारत को व्यापक संभावनाओं वाला क्षेत्र बना दिया है जहां आशा और प्रतिभा डिजिटल तरीके से अवसरों को पूरा करते हैं। भारत दुनिया के उन शीर्ष देशों में है जिन्होंने टेक्नोलॉजी और नवाचार का प्रभावी उपयोग करते हुए राज–व्यवस्था के दृष्टिकोण को सरकार–केन्द्रित से नागरिक केन्द्रित बना दिया है, जहां ई–सेवाओं के जरिए ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें सहभागितापूर्ण शासन व्यवस्था में नागरिकों का सशक्तीकरण हो और उन्हें निर्णय लेने तथा सरकारी नीतियां, कार्यक्रम और कायदे–कानून बनाने के कार्य में भागीदार बनाया जा सके। डिजिटल तरीके को अपनाने में इस शानदार बढ़त का अंदाजा संयुक्त राष्ट्र के 2018 के ई–गवर्नेंस इंडेक्स में भारत की स्थिति मे सुधार से स्पष्ट रूप से लगाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के इस सूचकांक से यह बात भी जाहिर हो जाती हैं कि शासन संचालन में सूचना और संचार टेक्नोलॉजी के उपयोग को भारत की क्षमता एषिया के तमाम अन्य देशों के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से बढ़ी है। भारत के संयुक्त राष्ट्र ऑनलाइन सेवा इंडेक्स में भी काफी सुधार हुआ है और यह 2018 में बढ़कर 0.95 पर जा पहुँचा है। नागरिकों के साथ संपर्क के लिए सषक्त मंच 'माईगॉव' (Mygov) का विकास और इस पर अमल सहभागितापूर्ण लोकतंत्र की सच्ची भावना से किया जा रहा है।

अपनी इस डिजिटल यात्रा में भारत तेज रफ्तार से 'उड़ान भरने' को है। डिजिटल आधारभूत ढांचे और विस्तारित डिजिटल पहुंच की मजबूत नींव रखने के बाद अब भारत विकास के अगले चरण में पहुंचने की तैयार कर रहा है जिसमें जबरदस्त आर्थिक लागत का सृजन होगा। यही नहीं, जैसे–जैसे अनुप्रयोगों का उपयोग शुरू हो रहा है, करोड़ों भारतवासियों का सशक्तीकरण हो रहा है।

आधार के माध्यम से भारत के नागरिकों को नयी डिजिटल पहचान मिली है और देश के एक अरब 22 करोड़ से अधिक निवासियों को इसके दायरे में लाया जा चुका है। उन्हें सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं जिनके जरिए कहीं भी और कभी भी अभिप्रमाणन का कार्य कराया जा सकता है। देश भर के गरीब तबके के लोगों के लिए तो ये पहचान पत्र वरदान की तरह बड़े राहत देने वाले साबित हुए हैं क्योंकि इसमें वे विभिन्न सामाजिक सेवाओं का फायदा बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। आधार को रसोई गैस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आदि से जोड़ दिया गया है जिससे लाभार्थियों की सही सही पहचान तो हो ही जाती है यह भी सुनिष्चित किया जा सकता है कि इन कल्याणकारी कार्यक्रमों का फायदा जल्द–से–जल्द सही व्यक्तियों तक पहुंचे। इसलिए डिजिटल अवसंरचना के निर्माण में 'आधार' का सीधा महत्व है और इसके माध्यम से सामाजिक व वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

महत्वाकांक्षी 'डिजीटल इंडिया कार्यक्रम' भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए निर्धारित किया गया है। डिजीटल इंडिया की प्रकृति रूपान्तरकारी है व इससे सुनिश्चित होगा कि सरकारी सेवायें नागरिकों को इलैक्ट्रौनिक रूप से उपलब्ध हों इस कार्यक्र का मकसद भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। प्रस्तुत लेख में इन्हीं परिप्रेक्ष्यों की चर्चा है।

देश में डिजिटल लेन–देन में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है ओर भुगतान में डिजिटल तरीका अपनाने में भारत कई पायदान ऊपर चढ़ गया है। जहां 2014–15 में 335 करोड़ डिजिटल लेन–देन हुए थे, वहीं 2017–18 में इनकी संख्या 2070.98 करोड़ तक पहुंच गयी। इतना ही नहीं, इनमें बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। डिजिटल भुगतान का फायदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में पूरा–पूरा उठाया जा रहा है जिससे जन कल्याण के प्रति सरकार की वचनबद्धता की फिर से पुष्टि होती है। अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत सरकार की ओर से दिये जाने वाले फायदे/सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। पैसे भेजने के इस तरीके में पलक झपने भर की देरी लगती है और सही राशि सही व्यक्ति तक पहुंच जाती है। अब 5.06 लाख कराड़े रूपये प्रत्यक्ष अंतरण इसके जरिए भेजे जा चुके हैं जिससे करीब 90,000 करोड़ रूपये की बचत हुई है। इस समय सरकार की करीब 434 योजनाएं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के दायरे में आती है।

डिजिटल से बदला परिदृष्य

डिजिटल इण्डिया ने सेवा उपलब्ध कराने और शासन संचालन के समूचे परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। कॉमन सर्विसेज सेंटर (साझा सेवा केन्द्र–सी.एस.सी.) देश में सूचना और संचार टेक्नोलॉजी से समन्वित ग्रामीण उद्यम हैं और नागरिकों को अनेक सेवाएं उनके घर के दरवाजे तक पहुंचाते हैं। इस समय देश भर के करीब 3.07 लाख सी.एस.सी. में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने जैसी 300 से अधिक सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। ग्राम स्तर के उद्यमों के माध्यम से इन केन्द्रों ने ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण स्थान बना दिया है जिससे डिजिटल तरीके से समावेशी सशक्त समाज के निर्माण में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गयी है और डिजिटल साक्षरता की खाई को पाटने में मदद मिली है।

डिजिटल बदलाव लोगों को डिजिटल यात्रा में संलग्न करने, उन्हें इसके लिए सक्षम व अधिकार संपन्न बनाने तथा यात्रा पर निकले लोगों की प्रगत का सिलसिला बनाए रखने की निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इसी दिशा में एक और प्रयास है 'डिजीलॉकर' यानी डिजिटल लॉकर जिसने लोगों को क्लाउड कम्प्यूअर की मदद से अपने दस्तावेज ओर प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रखने, साझा करने और उनका सत्यापन करने में सक्षम बनाया है। चूंकि दस्तावेज पर इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर रहते हैं और जारी करने वाले संगठन इन्हें साझा कर रहा होता है, इसलिए डिजिटल लॉकर में दस्तावेज जमा होने पर किसी दस्तावेज की सत्यापित प्रति या मूल प्रति जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कोई उपभोक्ता अपने शैक्षिक प्रमाणपत्रों को क्लिक का बटन दबाने भर से अपने संभावित नियोक्ता के साथ साझा कर सकता है। अब तक 1.59 करोड़ पंजीकृत उपभोक्ताओं ने 2.14 करोड़ दस्तावेज डिजीलॉकर में अपलोड किये हैं और इसमें नागरिकों को असीमित डिजिटल स्पेस निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल शिक्षा को बढ़ावा देने का माध्यम बन गया है। इसके जरिए विद्यार्थियों को आवेदन करने, आवेदन प्राप्ति की जानकारी हासिल करने, आवेदन की प्रोसेसिंग, स्वीकृति और आसानी से विभिन्न छात्रवृत्तियां प्राप्त करने जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। विभिन्न विभागों और उनकी छात्रवृत्तियों को बड़े पैमाने पर इसके दायरे में लिया गया है। 2015 में इसके शुभारंभ से 1.8 करोड़ विद्यार्थियों/लाभार्थियों को इसके माध्यम से 5,257 करोड़ रूपये संवितरित किये गये हैं।

ऑनलाइन पंजीयन प्रणाली (ओ.आर.एस.) ओर ई–हॉस्पीटल ने रोगियों को आधार संख्या पर आधारित ऑनलाइन पंजीयन सुविधा मुहैया करायी है और डॉक्टर से मुलाकात का समय प्राप्त करना आसान बना दिया है। इससे अस्पतालों में लगने वाली लंबी–लंबी कतारें कम हो गयी हैं और स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली कायम हो गयी है। देश के 318 अस्पतालों को ई–हॉस्पीटल सुविधा से जोड़ दिया गया है और 5.6 करोड़ ई–हॉस्पीटल लेनदेन इसके माध्यम से किये जा चुके हैं।

'जीवन–प्रमाण' से पेंशनभोगी अपने 'आधार' के बायोमीट्रिक से प्रमाणन विवरण का इस्तेमाल करके घर बैठे या बैंक, सी.एस.सी. केन्द्र अथवा सरकारी कार्यालय आदि में अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इस प्रमाण पत्र को हासिल करने और इससे जुड़ी सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए अब पेंशनर को सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की अनिवार्यता नहीं रह गयी है। अब तक करीब 1.75 करोड़ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 'जन्म प्रमाण' के माध्यम से बनाये किये जा चुके हैं।

लोगों को उनकी डिजिटल यात्रा पर निरंतर अग्रसर करते रहने के लिए यूनीफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस (नये जमाने के शासन संचालन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन–उमंग) शुरू किया गया है। यह मोबाइल ऐप अकेले ही 307 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराता है और इसके तहत 1200 से अधिक डिजिटल सेवाएं इकट्ठा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। नवम्बर 2017 में विमोचन के बाद 84 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने इसे डाउनलोड किया है।

रोज़गार सृजन

लोगों के जीवन का शानदार स्तर बनाए रखने के लिए रोजगार बुनियादी जरूरत है। भारत सरकार ने इस सिलसिले में इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण, बी.पी.ओ. संवर्धन, आई.ओ.टी. इंटरनेट ऑफ थिंग्ज जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पहल की है। भारतीय स्टार्ट अप्स इस जबरदस्त

बदलाव से उत्पन्न व्यापक संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए तरक्की कर रहे हैं। 2018 में 1,200 से अधिक स्टार्ट अप्स गठित किये गये जिनमें से 8 यूनीकार्न श्रेणी के थे। इस तरह देश में स्टार्ट अप्स की कुल संख्या 7,200 तक जा पहुंची है। मोबाइल टेलीफोनों का उत्पादन भी कई गुना बढ़ गया है। 2014 में देश में मोबाइल फोन बनाने वाली केवल दो इकाइयां थीं और आज 127 इकाइयां मोबाइल हैंडसेट और उनके हिस्से–पुर्जों का उत्पादन कर रही है। इससे रोजगार के 4.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर उपलब्ध हुए हैं। एकदम नये इलैक्ट्रोनिक्स विनिर्माण समूहों (ईएमसी) की स्थापना के लिए 20 स्थानों को मंजूरी दी गयी है और 23 आम सुविधा केन्द्र (सीएफसी) बनाए जाने हैं जिनसे रोजगार के करीब 6.5 लाख अवसर उतपन्न होंगे। बी.पी.ओ. आज देश के छोटे शहरों तक पहुंच चुके हैं और देश के 20 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों के 100 शहरें में इनका विस्तार है। इनसे इन छोटे शहरों और कस्बों में रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं और इनमें रहने वाले नौजवानों को सूचना टेक्नोलॉजी उद्योग का फायदा मिल रहा है।

डिजिटल व्यवधानों और लागतार बदलती अर्थव्यवस्था के साथ तेज रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए लोगों के कौशलों में भी लगातार सुधार करने और उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि लोग उन्हें अपना सकें। इसलिए डिजिटल साक्षरता बढ़ाना और भविश्य लिए लोगों को कौशल सम्पन्न बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान का उद्देश्य 6 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना है। 1 करोड़ 23 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था कितनी चिर–स्थायी बनी रहती है इसका दारोमदार इसके लचीलेपन और सुरक्षा में निहित है। उपयोग करने वालों को वित्तीय और अन्य डेटा के नुकसान की रोकथाम के लिए चेतावनी जारी करने के उददेश्य से साइबर स्वच्छता केन्द्र (बॉटनेट हटाने ओर मालवेयर विश्लेषण केन्द्र) स्थापित किया गाय है जो तत्काल बॉटनेट्स को हटाने की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसका उददेश्य लोगों को समावेशी, सुरक्षित और हिफाजत वाला साइबर स्पेस उपलब्ध कराना है।

सूचना टेक्नोलॉजी अब किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रह गयी है बल्कि इसका विस्तार सभी क्षेत्रों में हो रहा है। नयी और उदीयमान टेक्नोलॉजी अब कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रक्रियाओं को बदल और प्रभावित कर रही हैं। इन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जबरदस्त लागत पैदा की जा सकती है और इन क्षेत्रों की गतिशीलता और वितरण के मॉडल बदले जा सकते हैं। उभरती हुई टेक्नोलॉजी के प्रसार को ध्यान में रखते हुये फिनटेक और कृषि के क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, वर्चुअल रिएलिटी, ब्लॉकचेन, मेडिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों, नैनोइलेक्ट्रॉनिक्स आदि के क्षेत्र में उत्कृष्टता केन्द्रों (सी. ओ.ई.) की योजना बनायी जा रही है। इनसे अनुसंधान और नवसृजन के लिए एक उपयुक्त मंच उपलब्ध हो जाएगा जिससे स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष

भारत आज ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां डिजिटल इण्डिया की मजबूत नींव रखी जा चुकी है और सूचनाओं तथा सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाने से भारत को आर्थिक और सामजिक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की क्षमता के बेहतरीन उपयोग में मदद मिली है। इससे भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डालर (10 खरब डॉलर) की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहीं है और 2025 तक रोजगार के 5.5 से 6 करोड़ अवसरों की संभावना बन गयी है। एक ट्रिलियन डालर की इस अर्थव्यवस्था में 390–500 अरब डालर कृषि, स्वास्थ और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में डिजिटल अनुप्रयोगों से प्राप्त होंगे। इन सबसे न सिर्फ व्यापक आर्थिक बदलाव होगा बल्कि समावेशन, सशक्तिकरण और डिजिटल डिवाइड की खाई के पाटे जाने से (यानी कम्प्यूटर की जानकारी रखने वालों और इसमें असमर्थ लोगों के बीच का अंतराल दूर होने से) क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन भी आएगा और न्यू इण्डिया की बुनियाद पड़ेगी।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *S.C. dube, 1 Jan, 2005, Indian Society, National Book Trust, New Delhi.*
2. *K.S. Nipani, B.K. Murthi, 2017 Digital India, Vitasta Publications, New Delhi.*
3. *Arpan Kuar Kar, Suchi Sinha, M.P. Gupta, 2018, Digital India : Reflections and Practice, Springer, New York, USA.*
4. *NCERT, Indian Society, NCERT, New Delhi.*
5. *M. Senthil Kumar, S. Rigesh, 2017, Indian Society, Pearson, New Jersey USA.*
6. *Nadeem Hasnain, 2010, Indian Society and culture cantinuity and change, New Royal Book Company, Lucknow, U.P.*
7. *Ajay Kumar, 1 Jan 2018, Digital India, Prabhat Prakashan, New Delhi.*
8. *Ditial India Portal, website:digitalindia.gov.in*